ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

चार धाम मार्ग परियोजना में हुई बड़ी पर्यावरणीय चूक

रविवारीय, 02-08 अगस्त 2020 वर्ष- एक, अंक-52, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

ग्रीन रिवोल्ट के सभी प्रिय पाठकों को सावन पुर्णिमा एवं रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनायें।

थोड़ी सख्ती के बाद झारखंड में बैन किये गये प्लास्टिक के कैरी बैग फिर से प्रचलन में ,ऐसे में सवाल उठता है

कहां गया पॉलीथीन बैग पर रोक का आदेश ?

मुख्य संवाददाता

रांची : राज्य में पलास्टिक के थैलों पर रोक प्रहसन सा बन कर रह गया है। हालत ये है कि प्रशासन और दूकानदारों के बीच यह चूहे बिल्ली के खेल जैसा हो गया है।

कुछ महिने पहले तक जब प्रशासन प्लास्टिक के कैरी बैग पर रोक लगाने के लिये टीम लेकर दूकानदारों के यहां छापेमारी कर रहा था और प्रतिबंधित माइक्रोन के पॉलीथीन कैरी बैग मिलने पर अर्थदंड भी वसूला जा रहा था तब भय के मारे कुछ दिनों तक दूकानदारों ने इसका उपयोग बंद कर दिया था और दूकान के बाहर एक सूचना लिख कर ग्राहकों के लिये टांग दी थी कि कृप्या झोला लेकर आयें। लेकिन कोराना संकट के शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही प्रशासन भी सुस्त हो गया और दूकानदार से ग्राहक तक फिर से पॉलीथीन बैग का उपयोग धड़ल्ले से करने लगे हैं।

बाजार में फिर से सब्जी बेचने वालों से लेकर , ठेले वाले , फल वाले सभी इन्हीं प्रतिबंधित पॉलीथीन कैरी बैगों में सामान दे रहे हैं। ग्राहक भी बगैर थैला लिये ही बाजार जाते हैं उन्हें बाजार से प्लास्टिक कैरी बैग की ही आदत है। समस्या दूकानदारों के बजाय ग्राहकों से भी है कि वह कैरी बैग की ही मांग करते हैं।

एनजीटी का आदेश और माइक्रॉन का चक्कर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(NGT)ने प्लास्टिक और पॉलिथीन के इस्तेमाल के बारे में कई आदेश जारी किए हैं। 50 माइक्रोन से नीचे की प्लास्टिक की न तो मैन्युफैक्चरिंग और न ही सेल की जा सकती है। इस बैन में प्लास्टिक के वे डिस्पोजेबल कप और गिलास भी आते हैं जिन पर पतली पॉलिथीन की लेयर होती है या पतली प्लास्टिक से बने होते हैं। 50 माइक्रोन से ज्यादा के प्लास्टिक को री-साइकल किया जा सकता है, जबकि 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक के साथ ऐसा नही किया जा सकता। इस वजह से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है।

ऐसे पहचाने बैन किये गये कैरी बैग को :अगर थैली उंगली के जोर लगाने पर आराम से फट जाए तो समझ जाना चाहिए कि यह 50 माइक्रोन से कम पतली है। मार्केट में जितनी भी थैली लूज मिलती है, वह सारी ही एनजीटी की बैन की सीमा में आती है। बैन की सीमा के बाहर सिर्फ वही पॉलिथीन हैं, जिनका इस्तेमाल बड़ी कंपनियां अपने प्रॉडक्ट्स को पैक करने के लिए करती हैं। मिसाल के तौर पर दूध या ऑइल पैक करने की थैलियां। बेशक इन्हें आप आसानी से फाड़ नहीं सकते, इन्हें काट कर ही इस्तेमाल किया जा सकता है।

पॉलीथीन बैग के कचड़े ने पटना को डूबो दिया था

अब ये बातें पुरानी हो गयीं हैं कि प्लास्टिक के कचड़े को खाकर दुधारू मवेशी बीमार हो जाते हैं , खेतों में इसके डंप होने से उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है और ये सैकड़ो सालों तक जमीन में बने रहते हैं।

प्लास्टिक थैलों के कचड़ो ने पिछले साल पटना को बाढ़ में डूबो दिया था। ये बाढ गंगा के जलस्तर के कारण नहीं बल्कि भारी बारिश होने पर पटना के ड्रेनेज और नालियों के जाम होने के कारण हुआ था। सारे ड्रेनेज और शहर की नालियां प्लास्टिक कैरी बैग के कचड़े से जाम हो गयीं थीं और तेजबारिश में जलनिकासी न होने से पटना शहर जलमग्न हो गया था।

दुर्घटनामृत्यु की तरह माना जाएगा कोल इंडिया कर्मियों का कोरोना से निधनःप्रल्हाद जोशी

संवाददाता

रांची : कोयला, खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने अपने रांची दौरे के दौरान कहा कि कोरोना महामारी से होने वाला किसी कोल इंडिया कर्मी का निधन दुर्घटना मृत्यु माना जाएगा और कोल कर्मी के परिजनों को वो सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे, जो उन्हें कार्य के दौरान हुए दुर्घटना से निधन होने पर मिलते हैं। इस निर्णय से संविदा कर्मियों सहित कोल इंडिया के लगभग 04 लाख कर्मियों को लाभ मिलेगा। साथ ही, जिन कर्मियों का कोरोना के चलते अभी तक निधन हो चुका है, उनके परिजनों को भी इस निर्णय से सुरक्षा मिलेगी।

आश्रितों को मिलेंगे सभी लाभ

मंत्री ने वर्चुअल प्रेस कांन्फ्रेस के माध्यम से सीएमपीडीआई, रांची के 'मयूरी हॉल' से सभी मीडिया कर्मियों से सीधे संवाद किया । यह कार्यक्रम सीसीएल द्वारा आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कोल इंडिया कर्मी अपनी जान जोखिम में डालते हुए लगातार शानदार कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं उन्हें गर्व के साथ कोल योद्धा कहता हूं। मैंने यह घोषणा राष्ट्र को समर्पित उनकी अमूल्य सेवा को पहचान दिलाने के लिए की है। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कोयला खनन आने वाले वर्षों में झारखंड में विकास का एक नया दौर शुरू करेगा। व्यावसायिक कोयला खनन के लिए झारखंड की 09 कोयला खदानें आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई हैं, जिनसे राज्य को प्रति वर्ष 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही, राज्य के लोगों के लिए 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त राज्य को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) मद में भी प्रति वर्ष 17 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका उपयोग कोलफील्डस के आस-पास के क्षेत्रों के समावेशी विकास में किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि व्यावसायिक कोल खनन को शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। खासतौर पर झारखंड में आवंटन के लिए प्रस्तावित लगभग सभी खदानों में 05 से 10 आवेदक आवंटन हेतु आगे आए हैं। इससे राज्य को कई मायनों में लाभ पहुंचेगा और राज्य की प्रगति का नया अध्याय लिखा जाएगा।अपने रांची दौरे के दौरान मंत्री ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनके साथ राज्य में खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा की। साथ ही, उन्होंने कोयला कंपनियों ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल के प्रदर्शन की समीक्षा की और मौजूदा महामारी के बीच भी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कोल योद्धाओं द्वारा किए जा रहे कठिन परिश्रम की सराहना की।

इस बैठक में कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया, अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल, सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह, सीएमपीडीआई सीएमडी शेखर सरन सहित निदेशकगण एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। *पेज 3 भी देखें*

आदिवासी किसानों के बीच मूंगफली खेती को बढ़ावा

गरीबों का बादाम कही जाने वाली मूंगफली झारखंड में उगाई जाने वाली सरसों, तीसी के बाद तीसरी मुख्य तिलहनी फसल है

रांची :बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग के अध्यक्ष डॉ। जेडए हैदर बताते हैं कि झारखण्ड के काफी कम क्षेत्र करीब 23 हजार हेक्टेयर मात्र में मूंगफली की खेती होती है और इसकी उत्पादकता 1012 किलो प्रति हेक्टेयर मात्र है। जबकि पठारी क्षेत्र की वजह से प्रदेश की मिट्टी हल्की एवं बालुआही है, जो मूंगफली फसल के लिए उपयुक्त होती है। वर्षा आधारित इस फसल के अनेकों लाभ को देखते हुए राज्य में इसकी खेती की काफी संभावनाएं है।

चालु खरीफ मौसम में बीएयू के आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग में संचालित आईसीएआर - जनजातीय मूंगफली शोध उपपरियोजना के अधीन प्रदेश के आदिवासी किसानों के खेतों में मूंगफली की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह योजना आईसीएआर - मूंगफली शोध निदेशालय, जुनागढ़ (गुजरात) के सौजन्य से इस वर्ष लागु की गयी है।

पौधा प्रजनक एवं प्रभारी डॉ शशि किरण तिर्की ने बताया कि चालु खरीफ मौसम में मूंगफली की उन्नत किस्म गिरनार - 3 का अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण कराया गया है। गिरनार - 3 मूंगफली 110 से 115 दिनों में पककर तैयार होने वाली किस्म है। यह एक रोग सहिष्णु प्रजाति है, जो दोमट मिट्टी के लिये उपयुक्त होती है। इसमें तेल की करीब 51 प्रतिशत मात्रा पाया जाता है। इसके 100 दानों का वजन 50 ग्राम होता है। इसकी औसत पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति हैक्टेयर है।

इस कार्यक्रम में रांची एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के 7 प्रखंडो के 15 गाँवो के कुल 227 आदिवासी किसानों के करीब 12 एकड़ भूमि में उन्नत किस्म के मूंगफली की खेती को बढावा दिया जा रहा है। इनमें रांची के मांड़र प्रखंड के सोसई, गरमी व मलती, नगड़ी प्रखंड का चीपड़ा, कुदलोंग व सिमरटोला तथा कांके प्रखंड का अकम्बा, मुरुम, नगड़ी व दुबलिया प्रमुख गाँव है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोरा प्रखंड का सिरसोई व जेरबार तथा दालभूम प्रखंड का राजाबेरा आदि प्रमुख गांव है। इन गांवो के आदिवासी किसानों के बीच 10 क्विंटल मूंगफली किस्म गिरनार - 3 का बीज व अन्य उपादानों का वितरण किया गया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने किसानों को मूंगफली खेतीके लिये ट्रेनिंग दिया है।

डॉ तिर्की ने बताया कि झारखण्ड राज्य के रांची, लोहरदगा, गुमला और पूर्वी सिंहभूम जिले में मूंगफली की खेती अधिकतर होती है। अधिक उपज एवं जल्द तैयार होने वाली, सूखा सहिष्णु तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन से इसकी खेती से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। इसकी खेती में जल निकास की अच्छी सुविधा होना जरूरी है। प्रदेश के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने बिरसा मूंगफली -3, बिरसा मूंगफली -4 और बिरसा बोल्ड (बीएयू द्वारा विकसित) तथा आईसीजीभी - 9114, गिरनार - 3 , टीजी 37 ए तथा टीएजी - 25 किस्मों को अनुशंसित किया है।

मूंगफली के तेल का उपयोग रसोई कार्यों, वनस्पति घी व अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है। इसकी खली खाद व पशु आहार तथा छिलके ईंधन के रूप में काम आते हैं। मूंगफली में 25 से 30 प्रतिशत सुपाच्य प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई तथा फास्फोरस, कैल्शियम व लोहा जैसे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। अभी मूंगफली की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है। बाजार में अच्छी मांग होने के कारण किसान मूंगफली की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

मीडिया सेल (कुलपति कोषांग)बीएयू कांके, रांची

पर्यावरण बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करें सभी राज्यः एनजीटी

एजेंसियां

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सभी राज्यों में पर्यावरण की बहाली के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। एनजीटी द्वारा यह आदेश सभी राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रदूषण नियंत्रण समितियों के लिए जारी किया गया है। उन्हें सीपीसीबी के साथ मिलकर पर्यावरण की बहाली और जिला स्तर पर पर्यावरण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सीपीसीबी को उपलब्ध धन के उपयोग के लिए एक योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।

एनजीटी द्वारा यह आदेश 24 जुलाई, 2020 को जारी किया गया था। मामला उत्तरप्रदेश के बांदा, महोबा और चित्रकूट जिले में मैरिज हॉल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, अस्पताल, वाणिज्यिक परिसरों, होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अवैध संचालन से जुड़ा था। यह सभी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की बिना सहमति से चल रहे थे। इससे पहले एनजीटी ने 15 जुलाई, 2019 के अपने पिछले आदेश में कहा था कि यूपीपीसीबी ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभा पाने के लिए कर्मचारियों की कमी को कारण बताया था। इस वजह से वो अपनी क़ानूनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए थे। इस बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को स्थिति की समीक्षा करने और उसपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

24 जुलाई को जब यह मामला फिर से एनजीटी के समक्ष आया तो यह देखा गया कि मुख्य सचिव ने अब तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। साथ ही यूपीपीसीबी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें भी खामियां हैं। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें पर्यावरण की बहाली के लिए मिले फंड को प्रदूषण नियंत्रण कक्षों की स्थापना पर खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या यह एक तरह का पूंजी निवेश है! कोर्ट के आदेशानुसार पर्यावरण की बहाली के लिए मिला फंड पर्यावरण को फिर से पुरानी स्थिति में लाने के लिए था। इसके अंतर्गत पर्यावरण के सतर्कता तंत्र को मजबूत करना और उसकी निगरानी के लिए प्रयोगशालाओं को स्थापित करना शामिल था। इसके साथ जिला मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर जिला स्तर पर पर्यावरण सम्बन्धी योजनाएं तैयार करना शामिल था। साथ ही बहाली के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की मदद लेना और प्रदूषित स्थानों का अध्ययन और उसको प्रदूषण मुक्त करना शामिल था।

कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आदेश दिया है कि वो सीपीसीबी की मदद से अपनी कार्ययोजना पर दोबारा विचार करें और दो महीनों के अंदर सीपीसीबी की मंजूरी के बाद अपनी योजना को अंतिम रूप दें।

रांची रेलवे स्टेशन पर कोविड केअर वेंडिंग मशीन लगायी गयी

रांची : 30 जुलाई 2020 को रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर कोविड केअर वेंडिंग मशीन लगाया गया। इस मशीन के द्वारा यात्री शुल्क देकर मास्क, सैनिटाइजर एवं ग्लव्स प्राप्त कर सकते है ।

तीन लेयर वाले दो मास्क का न्यूनतम शुल्क 10 रुपये, 100`' सैनिटाइजर का शुल्क 50 रुपये है तथा हैंड ग्लव्स का शुल्क 20 रुपये हैं । कोरोनावायरस के इस संक्रमण काल में जब मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना अति आवश्यक है इस स्थिति में राँची रेलवे स्टेशन पर लगा यह मशीन यात्रियों के लिए बहुत ही उपयोगी है ।

लोकजीवन में समाहित जल की छटाएं

डॉ.कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हिन्दी में लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है । आपके 250 से अधिक लेख तथा 22 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, शताब्दी सम्मान,राजभाषा भूषण पुरस्कार, इस्वा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉ.मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

भौतिक रूप से जल एक रंगहीन पदार्थ है। लेकिन लोकजीवन में जल की अनेक रंग, उसकी अनेक छवियां मौजूद हैं। जल जिस भी रंगीन पदार्थ के साथ मिलाया जाता है उसी का रंग अख्तियार कर लेता है। इस धरती पर पेड़-पौधे, पक्षी, मनुष्य, समेत सभी प्राणियों के जीवन का मूलाधार है। धरती पर व्याप्त हरियाली और खुशहाली के पीछे जल है। कहीं पेड़ों पर पक्षियों का सुन्दर कलरव है, तो कहीं झरने का मनोहारी कलकल, छलछल। इनके पीछे जल की भूमिका है। जल के स्वर, संगीत तथा लय भी हैं। नदियों, जलधाराओं, जल प्रपात, वर्षा, हिमपात, जैसे विविध रूपों में यह जल हमारे जीवन में रंग भरने का काम करता है।

भारतीय संस्कृति एवं लोक जीवन में जल को अपूर्व स्थान प्राप्त है। हमारे राष्ट्रगीत में जल को 'सुजलाम सुफलाम' से विभूषित किया गया है जो इसी सनातन चेतना का द्योतक है। आयुर्वेद के पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। आयुर्वेद में जल को अमृत तुल्य माना गया है। जल में चिकित्सकीय गुण होते है। जल चिकित्सा इसी अवधारणा पर आश्रित है। आयुर्वेद में जलनेती इसी तरह की एक पंचकर्म चिकित्सा पद्धति है। दार्शनिकों, रचनाकारों तथा विचारको ने जल को विविध रूपों में देखा, समझा है, और उसका वर्णन किया है। महासागर से शुरू होकर वाष्प, बादल तथा फिर वर्षा के रूप में धरती पर गिरने वाले जल के अनेकानेक मार्गों से होते हुए पुनः समुद्र में पहुंचने को

'जलचक्र' कहा जाता है। इसी चक्रीयता के रूपक में कबीर ने 'बूंद समानी समद में', कहकर जीवन यात्रा का दार्शनिक निचोड़ प्रस्तुत किया है। जल के अविरल प्रवाह को निर्मलता का पर्याय माना गया है। भाषा के बारे में अक्सर कहा जाता है- भाषा बहता नीर। भाषा बहते जल के समान है जो अपने प्रवाह के साथ अपने को नित निर्मल तथा ग्राह्य बनाए रखती है।

भारत की वैविध्यपूर्ण संस्कृति को जल के संदर्भ में व्याख्यायित करते हुए एक कहावत प्रसिद्ध है- कोस-कोस पर बदले पानी,चार कोस पर बानी। यानी हमारे देश में हर कोस पर पानी की प्रकृति बदल जाती है, तथा हर चार कोस पर भाषा की तासीर में परिवर्तन हो जाता है। लोक में व्याप्त ये कथन देश की सांस्कृतिक विविधा का सुन्दर निरूपण करते हैं। इसी तरह लोकजीवन में जल की अनेक मनोहारी छटाएं मिलती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मानव जीवन के हर पक्ष तथा पहलू से जल अनंतकाल से अन्यतम रूप से जुड़ा है। सभ्यता के उषाकाल से ही जल मानव की यात्रा का साक्षी तथा सहभागी रहा है तथा यह यात्रा आज भी अनवरत जारी है। चरैवेति ! चरैवेति !!

पानी प्रकृति की सबसे अनमोल भेंट है। जीवन के हर क्षेत्र में जल की अनेक रूपों में उपयोगिता है। हमें चाहिए कि हम जलस्रोतों को सहेजें, संरक्षित रखें तथा उन्हें प्रदूषित होने से बचायें। हमारा दायित्व है कि हम इस कीमती संसाधन को संभालकर रखें, तथा इसका विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करें। हमें जल की फिजूल खर्ची को रोकना ही होगा। इन बातों के लिए देश भर में व्यापक जन जागरण करना होगा। यदि हम जल को लेकर दीर्घकालीन ठोस नीति तय करने में असफल रहे, तो दो तीन दशकों के बाद यह राष्ट्रव्यापी संकट बन सकता है। नगरों, कस्बों के साथ-साथ देश के दूर दराज के गांव देहात में रहने वाले नागरिकों को भी स्वच्छ पेयजल मिले, यह हम सभी का राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। यह भी ध्यान रहे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त जल सुलभ रहे, यह सुनिश्चित करना हम सभी का सामाजिक तथा राष्ट्रीय दायित्व है। *इलेक्ट्रॉनिकी आप के लिये से साभार*

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

दक्ष होगा हमारा युवा

चीन , जापान, कोरिया, जर्मनी जैसे देशों में 70-80 प्रतिशत युवा अपनी उच्च शिक्षा के समापन के साथ ही किसी रोजगारपरक विधा में भी दक्ष हो जाते हैं। क्योंकि उनके यहां स्कूली शिक्षा के दरम्यान ही छात्रों को रूचि के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष की पढाई का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाता है। अब केंद्र सरकार ने भी देश में स्कूली शिक्षा के समय से ही छात्रों को किसी क्षेत्र विशेष में दक्ष बनाने के लिये सिलेबस में बदलाव किया है। यह समय के साथ चलने वाला एक बहुत ही अच्छा निर्णय है।

अब तक हमारे युवा सिर्फ एम ए, बीए की डिग्री लेते रहे हैं, पर वो स्किल्ड नहीं होते। आज बदलती दुनिया और जरूरतों में सिर्फ सामान्य डिग्री से कोई रोजगार भी नहीं मिलता। देश में एक परंपरा सी रही है कि पहले ग्रेजुएशन तक डिग्री लेने के लिये पढो उसके बाद किसी रोजगारपरक शिक्षा की ओर समय दो। इसमें धन और समय दोनो की बर्बादी होती है।

देश में एक और बड़ी समस्या है कि किसी अच्छी योजना और प्रयास के बीच भ्रष्टाचार का होना या खानापुर्ति कर काम को ठोस रूप से जमीन पर न उतरने देना। स्कूली पढाई के दरम्यान परंपरागत विषयों के साथ ही किसी व्यावसायिक विषय की पढाई को सिर्फ खानापुर्ति बनने से रोकने होगा। इस प्रयास को ठोस रूप में जमीन पर उतारने में लग जाना होगा। ये वर्तमान नहीं भविष्य में भी आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम होगा। हमने इस कदम को उठाने में देर कर दी है, पर वर्तमान से भी शुरूआत होने से भविष्य की युवा शक्ति ज्यादा सक्षम होगी। आखिर आज चीन जैसे देश इसी दक्षता के बल पर ही तो दुनिया के सामने ताल ठोकते हैं।

सरकार ने युवाओं को स्किल्ड बनाने की जो भी योजनायें शुरू कीं उसमें से जयादतर की जमीनी हकीकत क्या है?

बहुत सारे एनजीओ ने युवाओं को किसी रोजगारपरक विधा में दक्ष करने का काम ले लिया, जोड़ तोड़ कर उसके लायक सुविधायें भी दिखा दी। लेकिन हकीकत में इनका ज्यादतर काम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। फर्जी आंकड़ा और ट्रेनिंग के नाम पर खानापुर्ति होती रही है। यहां तक कि पशुपालन विभाग ने भी झारखंड में ग्रामीण युवाओं को जो पशुचिकित्सा का प्रशिक्षण दिया है उसमें भी ग्रीनरिवोल्ट ने जो जानकारिया जुटाई और तहकीकात की तो विभाग के दावे झूठे ही प्रतीत हुये। इस क्षेत्र में जमीन पर ठोस काम किये जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण देने या स्किल्ड बनाने के नाम पर खानापुर्ति को रोकना ही होगा।

बाघ के लिए अधिक खूंखार है आदमी

जयसिंह रावत

बाघ या बड़ी बिल्ली परिवार का कोई भी सदस्य भरे-पूरे वन्यजीव संसार का संकेतक या मापक और स्वस्थ-संतुलित पर्यावरण का प्रतीक होता है,इसलिए इस अति महत्वपूर्ण जीव के विलुप्ति के कगार तक पहुंच जाने से चिंतित बाघों की मौजूदगी वाले 13 देशों ने सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी कर 6 हजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। हर्ष का विषय है कि भारत ने इस संकल्प को लक्ष्य वर्ष से काफी पहले ही हासिल कर लिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम बड़ी संख्या में शिकारियों के हाथों बाघों की मौतों से आखें मूंद ले। हर साल एक -एक बाघ पर करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी पिछले लगभग एक दशक में देश में प्रतिवर्ष बाघों की मौतों का औसत 94 रहा, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें केवल शिकारियों के हाथों हुई हैं।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 17 राज्यों में स्थित 50 टाइगर रिजर्वों को 49,067 करोड़ 79 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। यह राशि भी टाइगर रिजर्वों से बाहर के लिये नहीं थी। इस प्रकार देखा जाएतो एक बाघ की सुरक्षा के लिये प्राधिकरण द्वारा लगभग 16.53 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गत वर्ष जारी बाघ गणना के परिणामों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2,967 हो गयी है, जबकि 2008 की गणना में 1,411, वर्ष 2010 में 1,706 और 2014 की गणना में बाघों की संख्या 2,226, मानी गयी थी। इन वर्षों में बाघों की संख्या में लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ ही बुरी खबर यह है कि 2012 से लेकर 2019 के बीच देश में 750 बाघों की मौत हुई है और इनमें से 168 की मौत शिकारियों के हाथों हुई, जबकि 70 मौतों का पता लगाना बाकी था। इनके अलावा 369 मौतें दुर्घटना, आपसी लड़ाई, अधिक उम्र और भूख आदि प्राकृतिक कारणों से हुई है।

संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और बाघों का या किसी भी जीव का स्वाभाविक मौत मरना भी जरूरी ही है। अगर बाघ की असंतुलित वृद्धि हो जायेगी तो वह शाकाहारियों की नस्लें ही समाप्त कर देगा जिससे आहार श्रृंखला टूटने के साथ ही पादप जगत भी असंतुलित हो जाएगाा। वैसे भी अकेले बाघ या मांसाहारी का अस्तित्व संभव नहीं है। बाघ को जंगल का राजा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उसकी छत्रछाया में लाखों की संख्या में अन्य जीव प्रजातियां पनपती हैं। बुढ़ापा, दुर्घटना और बड़े और ताकतवर जीव से लड़ाई में मौतें हो जाना भी अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन बाघों के अस्तित्व के लिए असली खतरा आधुनिक हथियारों से लैस और चालाक आदमी से है। आदमी इन मांसाहरी जीवों को अपने ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने, वस्त्र बनाने, हड्डियों से औषधीय सामग्री बनाने, दांत और मूंछ आदि से टोने-टोटके करने आदि के लिये मार डालता है। बहादुरी दिखाने के लिए इन बेकसूर जीवों को गेम के लिए मार डालना भी शाही शौक प्राचीन काल से चला आ रहा है। एक अनुमान के अनुसार मनुष्य ने बीसवीं सदी से लेकर अब तक विश्व में बाघों की 90 प्रतिशत आबादी को समाप्त कर दिया है।

पूर्व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अनिल माधव दवे ने 10 अप्रैल 2017 को राज्यसभा में कहा था कि वर्ष 2014 से लेकर 2016 के बीच बाघों के शिकार की वारदातों में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में जहां बाघों की हत्या की 14 वारदातें दर्ज हुईं थीं वहीं 2016 में ये वारदातें बढ़ कर 42 हो गईं। स्वैच्छिक संगठन 'वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में देश में 110 बाघों और 493 गुलदारों की मौतें हुई हैं जिनमें से 38 बाघों और 128 गुलदारों की मौतें शिकारियों के हाथों हुई हैं।

शिकार की सर्वाधिक 29 वारदातें मध्य प्रदेश में, 22 महाराष्ट्र में तथा 12-12 उत्तराखण्ड और कर्नाटक में हुईं। उससे पहले 2018 में शिकारियों के हाथों 34 बाघ मारे गये थे। गत वर्ष देश में शिकारियों द्वारा 128 गुलदार भी मारे गये। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2008 से लेकर 2018 के बीच देश में शिकारियों ने 429 बाघ मारे।

चिन्ता की बात यह है कि हर साल अरबों रुपये खर्च करने पर भी बाघों का निर्मम संहार नहीं रुक रहा है। देश में नवीनतम गणना में कुल 2,967 बाघ पाये गये, जो कि बाघों की वैश्विक संख्या का 75 प्रतिशत है। फिर भी शिकारियों के हाथों राज्य सरकार 12 बाघों को नहीं बचा पाई। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) द्वारा बाघों के संरक्षण के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में देश के 17 राज्यों में स्थित 50 टाइगर रिजर्वों को 49,067 करोड़ 79 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया। यह राशि भी टाइगर रिजर्वों से बाहर के लिए नहीं थी। इस प्रकार देखा जाएतो एक बाघ की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा लगभग 16.53 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। चूंकि वन एवं वन्यजीव अब संविधान की समवर्ती सूची में हैं, इसलिए इस राशि में केंद्रांश 28,565 करोड़ 36 लाख था और शेष राशि राज्य सरकारों को खर्च करनी थी। अगर केंद्रांश पर ही गौर करें तो एक बाघ को बचाने के लिए पिछले साल केन्द्र सरकार ने अपनी ओर से 7.12 करोड़ रुपये रखे थे। केंद्रांश का 2,986 करोड़ मध्य प्रदेश और 3709 करोड़ से अधिक महाराष्ट्र को गया जहां बाघों की सर्वाधिक हत्याएं हुई हैं। इस मद में 1,794 करोड़ उत्तराखण्ड को भी मिले, फिर भी शिकारियों के हाथों राज्य सरकार 12 बाघों को नहीं बचा पाई। देखा जाए तो उत्तराखण्ड के 442 बाघों को बचाने पर केवल केन्द्र सरकार की ओर से प्रति बाघ 4 करोड़ से अधिक की रकम राज्य सरकार को मिली। वन्यजीव जीवों से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए 2006 में गठित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के खर्चों के लिये ही सरकार ने इस साल 14 करोड़ का बजट रखा है, जिसमें 7 करोड़ तो केवल वेतन के लिये और 20 लाख रुपये मुखबिरी के लिए हैं।

इंदिरा गांधी ने बाघों के पर्यावरणीय महत्व एवं उनकी घटती संख्या को देखे हुये 1973 में 9 टाइगर रिजर्व स्थापित किए थे जिनकी संख्या आज 50 हो गई है। उसी दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना जिसमें संशोधन होते रहे। फिर भी स्थानीय समुदाय को दुश्मन मानते हुए उनके हितों को दरकिनार कर शुरू किए गए प्रयास वन्यजीवों की सुरक्षा की गारण्टी नहीं दे सके। सबसे दुखद कि कुछ साल पहले उड़िसा के चीड़ियाघर में बाघ को मार कर उसकी खाल तक उतार ली गयी थी।

2021 में बहुत सारे नेक इरादों की जरूरत है

मुरलीधर

पृथ्वी, वन, पर्यावरण के लिये कई महत्वपूर्ण देशों में तो हाल के वर्षों में व्यापक मुद्दों पर जन आंदोलन आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि प्रमुख समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी जीवन मूल्यों में इधर बहुत बिखराव आया है।

नये साल के आगमन पर हम स्वाभाविक तौर पर बेहतर जीवन के बारे में सोचते हैं। विचार करते हैं कि जो गलतियां बहुत हानिकारक सिद्ध हो रही हैं, उन्हें अब दृढ़ निश्चय करके सुधार लिया जाए। इस बारे में भी सोचते हैं कि जो कार्य बहुत सार्थक हैं, उन्हें निष्ठा व मेहनत से आगे बढ़ाएं। यदि इस सोच को हम व्यक्तिगत स्तर पर न लेकर विश्व की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में देखें तो पाएंगे कि दुनिया को वर्ष 2021 के आरंभ में ऐसे नेक इरादों की जितनी जरूरत है, उतनी शायद पहले कभी नहीं थी। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि धरती पर हजारों वर्ष से फलने-फूलने वाले विविधता भरे, रंग-बिरंगे, खूबसूरत जीवन को खतरे में डालने वाली स्थितियां मानव-निर्मित कारणों से इतनी विकट पहले कभी नहीं हुई थीं, जितनी आज हैं। यह स्थिति एक ओर पर्यावरणीय विनाश से जुड़ी है, दूसरी ओर महाविनाशक हथियारों से। धरती की जीवनदायिनी क्षमता को खतरे में डालने वाली समस्याओं को नियंत्रित करने का समय निकलता जा रहा है।

ठोस कार्रवाई जरूरी

इस बारे में वैज्ञानिक निरंतर चेतावनी देते रहे हैं कि एक 'टिपिंग पॉइंट' के बाद कुछ पेचीदा पर्यावरणीय समस्याएं मानवीय प्रयास द्वारा नियंत्रित होने की क्षमता से बाहर निकल सकती हैं। दूसरा कारण यह है कि इन समस्याओं के समाधान के संदर्भ में विश्व नेतृत्व से जो उम्मीद रही है, वह तेजी से धूमिल होती जा रही है। बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे हैं, विशेषज्ञों की रिपोर्टें तैयार होती रही हैं, पर इन सब के बावजूद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, परमाणु हथियारों के विस्तार का व उनके वास्तविक उपयोग का खतरा भी प्रत्यक्ष दिखने लगा है।

ऊपरी तौर पर चाहे आज की दुनिया में बहुत चमक-दमक नजर आए, पर सचाई यही है कि जीवन-रक्षा की दृष्टि से आज स्थिति पहले ही बहुत विकट है और निकट भविष्य में और अधिक विकटता की ओर बढ़ती नजर आ रही है। इस बात से सहमत लोग भी कह सकते हैं कि स्थिति भले ही वास्तव में इतनी गंभीर हो, पर इरादे चाहे नव वर्ष के हों या किसी अन्य समय के, महज नेक इरादों से क्या होगा? जाहिर है, जरूरत सिर्फ नेक इरादों की नहीं, इन पर आधारित ठोस कार्रवाई की है, जो अभी विश्व स्तर पर नजर आ नहीं रही है। यह सही है कि जरूरत वास्तविक ऐक्शन की है, ठोस कार्रवाई की है, पर अभी इसके अनुकूल सोच भी व्यापक स्तर पर नजर आए तो उससे निराशा के माहौल में आशा की किरण मिल सकती है। ऐसी आशा की किरण ही यदि वर्ष 2021 के आरंभिक कुछ महीनों में विश्व स्तर पर नजर आने लगे तो अभी के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि, एक महत्त्वपूर्ण शुरुआत होगी। इस समय चिंता की बात तो यह है कि यदि नेक इरादे भी विश्व स्तर पर इतने नजर नहीं आ रहे हैं, जितने की जरूरत समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए लगती है। जहां तक विश्व के सबसे शक्तिशाली व असरदार देशों के नेतृत्व का सवाल है, तो वह परमाणु शस्त्रों को समाप्त करने और ग्रीन हाउस गैसों को समयबद्ध ढंग से कम करते जाने जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर बुरी तरह पिछड़ रहा है। अमेरिका जैसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश, जो झिझकता हुआ ही सही, पहले कुछ आगे बढ़ा था, हाल के समय में लगातार पीछे हटता नजर आया है। कुछ ही दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पेरिस समझौते से हटने की घोषणा की। जाहिर है, इसका असर अन्य मुल्कों पर भी पड़ेगा। सच तो यह है कि जिन देशों का रिकॉर्ड इन मामलों में अपेक्षाकृत बेहतर है, वे भी अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं।

पृथ्वी को लेकर विश्व नेतृत्व की इस विफलता की पूर्ति केवल तभी हो सकती है, जब संसार की सबसे बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए जन-शक्ति या नागरिकों की सजगता के स्तर पर कोई बड़ा उभार आए। इस तरह के उभार से यह उम्मीद निकलती है कि भले ही विश्व नेतृत्व इस समय असफल हो रहा हो, पर लोकतांत्रिक दबाव में उसको आगे चलकर इन समस्याओं के लिए कहीं अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से इस तरह का नेतृत्व आगे आएगा जो प्रमुख समस्याओं के लिए कहीं अधिक प्रतिबद्ध व निष्ठावान हो। पर नागरिकों की सजगता का ऐसा कोई बड़ा उभार भी अभी विश्व स्तर पर नजर नहीं आ रहा है।

इस व्यापक संदर्भ में हमें नववर्ष की चुनौतियों का जायजा लेना है और उनसे जुड़ी तैयारी के बारे में सोचना है। नव वर्ष के नेक इरादों के बारे में एक सोच हमारी अपनी है, जो हमारे निजी जीवन के सरोकारों से, स्वस्थ जीवन और नजदीकी संबंधों से जुड़ी है। इसके साथ एक व्यापक सामाजिक संदर्भ में भी नेक इरादे जरूरी हैं। सभी संकीर्ण सीमाओं को पार करते हुए एक व्यापक समझ जरूरी है कि विश्व स्तर पर मौजूद कुछ बड़ी समस्याएं हमसे समयबद्ध समाधान की मांग कर रही हैं। इस बारे में हमें व्यापक, सार्थक समझ विकसित करनी है और अपने जीवन को इन समाधानों से जोड़ना है। यदि इस समझ के साथ हम नए वर्ष के आगमन को देखें तो यह हमारे लिए भी सार्थक होगा और विश्व पर्यावरण, वायु, जल, प्राणी मात्र वाले इस दुनिया के लिए भी।

खरीफ फसलों के बुवाई रकबे में 13.92 प्रतिशत की वृद्धि

जूट और मेस्ता को छोड़कर सभी फसलों के बुवाई का रकबा बढ़ा

नई दिल्ली : कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों और कृषि गतिविधियों की सुविधा के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं। इस दौरान खरीफ फसलों के बुआई रकबे में संतोषजनक वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 774.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस वर्ष 31 जुलाई, 2020 तक खरीफ फसलों का बुवाई रकबा 882.18 लाख हेक्टेयर है। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की तुलना में बुवाई रकबे में 13.92% की वृद्धि हुई है।

चावल : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 223.96 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल की बुवाई लगभग 266.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।

दलहन : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 93.84 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन की बुवाई लगभग 111.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।

मोटे अनाज : पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 139.26 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज की बुवाई लगभग 148.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।

तिलहन: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 150.12 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन की बुवाई लगभग 175.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।

गन्ना: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.20 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने की बुवाई लगभग 51.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।

जूट और मेस्ता: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.05 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट और मेस्ता की बुवाई लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है।

कपास: पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 108.95 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास की बुवाई लगभग 121.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है इसलिए, कुल मिलाकर, खरीफ फसलों के तहत बुवाई क्षेत्र कवरेज की प्रगति पर कोविड -19 का कोई प्रभाव नहीं है।

पक्षियों के मल में ऐसे रोगाणु पाए जा रहे हैं जिन पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक का असर

अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के पर्यावरण इंजीनियरों ने एंटीबायोटिक रजिस्टेंट को लेकर पक्षियों पर एक अध्ययन किया है।

कुछ समय पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) द्वारा किए गए एक अध्ययन में, चिकन में एंटीबायोटिक अवशेषों के मिलने का पता चला था। एंटीबायोटिक का उपयोग मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए ही नहीं बल्कि वजन बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा था। इसके कारण एंटीबायोटिक प्रतिरोधक बैक्टीरिया उभरने के बारे में बताया गया था। अब अमेरिका की राइस यूनिवर्सिटी के पर्यावरण इंजीनियरों ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध (रजिस्टेंट) को लेकर पक्षियों पर एक अध्ययन किया है।अध्ययनकर्ताओं के मुताबिक, पक्षियों का उनके शिकार होने से ज्यादा, स्वास्थ्य पर एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा है। यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत खतरनाक है। अध्ययन के अनुसार आम शहरी बतख, कौवे और गुल के मल में उच्च स्तर के जीन पाए गए हैं, जो रोगाणु एंटीबायोटिक प्रतिरोधक हैं। यह अध्ययन जर्नल एनवायर्नमेंटल पलूशन में प्रकाशित हुआ है। अध्ययनों से पता चला है कि पक्षी के माध्यम से ले जाई गई एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन (एआरजीएस) और बैक्टीरिया- तैराकी, मल, प्रभावित मिट्टी के संपर्क में आने से अथवा महीन कणों के माध्यम से ये मनुष्यों तक पहुंच सकते हैं। अध्ययन में एआरजी हॉटस्पॉट के पास पाए जाने वाले पक्षी के मल का भी विश्लेषण किया गया है ।

वैज्ञानिकों ने बनाया पेड़ में कीड़ों का पता लगाने वाला डिवाईस

वर्तमान में कीड़ों को पहचानने के लिए जो विधि प्रयोग की जा रही है उसके लिए नमूनों को पहले परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजना पड़ता है जिसमें काफी समय लग जाता है लेकिन अब वैज्ञानिकों ने डीएनए आधारित पोर्टेबल डिवाइस को बनाने में सफलता हासिल की है, जो दो घंटों के अंदर पेड़ में लगे कीड़ों का पता लगा सकता है इसके लिए जटिल प्रक्रियाओं और केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है यह डिवाइस यूनिवर्सिटी ऑफ़ ब्रिटिश कोलंबिया द्वारा बनाया गया है जिससे जुड़ा शोध जर्नल प्लोस वन में प्रकाशित हुआ है। कीट का पता लगाने के लिए पत्तियों, शाखाओं के हिस्सों या कीटों के पंखों और अन्य छोटे नमूनों को एक ट्यूब में रख दिया जाता है यह डिवाइस इस कीट के डीएनए को डेटाबेस में मौजूद प्रजातियों के जीनोमिक डेटा से मिलान करता है यदि डाटा मेल खाता है तो यह सिग्नल उत्पन्न करता है जिसे इससे जुड़े स्मार्टफोन की मदद से प्रदर्शित किया जा सकता है ।

दूध नहीं एंटीबायोटिक पीता है इंडिया?

राजेश्वरी सिन्हा

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अपने अध्ययन में पाया है कि जब कोई डेरी किसान अपने मवेशियों को एंटीबायोटिक देता है तो प्रबल आशंका होती है कि वह दूध के माध्यम से मनुष्यों के शरीर में पहुंच जाए

डेयरी में पशुओं को एंटीबायोटिक देना आम है। बहुत बार दूध उन बीमार पशुओं से प्राप्त होता है जिन्हें एंटीबायोटिक की भारी खुराक दी जाती है डेरी में पशुओं को एंटीबायोटिक देना आम है। बहुत बार दूध उन बीमार पशुओं से प्राप्त होता है जिन्हें एंटीबायोटिक की भारी खुराक दी जाती है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में रहने वाले डेरी किसान खैरातीलाल चोकरा अपनी गाय या भैंसों के बीमार पड़ने पर उन्हें एंटीबायोटिक की तगड़ी खुराक देते हैं। एक सिलसिला हफ्ते में दो या तीन जारी रहता है। उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाले अन्य डेरी किसान सौरभ श्रीवास्तव भी अपने पशुओं को लगातार तीन दिन तक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं। संक्रमण से पशुओं के स्तन ग्रंथि में आई सूजन को दूर करने के लिए वह ऐसा करते हैं। एंटीबायोटिक देने के बाद दूध का रंग बदल जाता है और उससे अजीब सी दुर्गंध आने लगती है। श्रीवास्तव बताते हैं, ''दूध का रंग ऐसा हो जाता है जैसे उसमें खून मिल गया हो।'' चूंकि दूध बेचकर ही उनका जीवनयापन होता है, इसलिए पशुओं को स्वस्थ रखना उनके लिए बहुत जरूरी होता है। चोकरा के पास 20 गाय व भैंस है, जबकि श्रीवास्तव के पास कुल 92 गाय व भैंस हैं। ये पशु ही उनके जीवन का आधार हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 2018 में देशभर के संगठित और असंगठित क्षेत्र के दूध के नमूनों की जांच की थी। जांचे गए 77 नमूनों में एंटीबायोटिक के अवशेष स्वीकार्य सीमा से अधिक पाए गए थे। लेकिन खाद्य नियामक ने यह नहीं बताया कि ये कौन से एंटीबायोटिक थे या किस ब्रांड के थे। दिल्ली स्थित गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) ने इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया, लेकिन लगातार फॉलोअप और अपील के बाद भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिली।

एंटीबायोटिक के दुरुपयोग और दूध में इसकी मौजूदगी के कारणों का पता लगाने के लिए सीएसई ने प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों-पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसानों समेत तमाम हितधारकों से बात की।

बीमारी की मजबूरी

किसान सबसे अधिक परेशान थनैला रोग से होते हैं। पशुओं को होने वाला यह सामान्य रोग है। गलत कृषि पद्धति और दूध दुहने में साफ-सफाई की कमी के कारण पशुओं को यह रोग हो जाता है। अगर कोई पशु दूध दुहने के बाद गंदी जगह बैठ जाता है तो सूक्ष्मजीव थनों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर पशु को बीमार कर देते हैं। दूध दुहने वाला अगर साफ-सफाई से समझौता कर ले या दूध दुहने में गंदे उपकरणों का इस्तेमाल करे, तब भी थनैला रोग हो सकता है। यह बीमारी विदेशी नस्ल के दूधारू पशुओं और क्रॉसब्रीड पशुओं में बहुत सामान्य होती है।

किसान अस्पतालों के चक्कर काटकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए आमतौर पर इस बीमारी का इलाज खुद ही करते हैं। कर्नाटक में कौशिक डेरी फार्म के संचालक पृथ्वी कहते हैं, ''अधिकांश मौकों पर सरकारी चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते। कंपाउंडर फार्म में आते हैं लेकिन उन्हें बीमारी या उपचार की बहुत कम जानकारी होती है।'' वह अन्य किसानों से वाट्सऐप के माध्यम से समस्या पर चर्चा करते हैं और चिकित्सक से फोन पर ही बात कर लेते हैं। निजी चिकित्सकों की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दवाएं बिना चिकित्सक के परामर्श पर आसानी से मिल जाती हैं।

सीसीएल ने ओबीएस का चेक श्रीमती रेखा देवी को सौंपा

रांची सी.सी.एल. ऑफिसर्स बेनिवोलेन्ट सोसाईटी (ओ.बी.एस.) की ओर से 31 जुलाई को सीसीएल मुख्यालय,दरभंगा हाउस, रांची में सीसीएल के निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना)भोला सिंह ने स्व. बिन्देश्वरी प्रसाद, पूव प्रबंधक (खनन) जो केओसीपी, हजारीबाग क्षेत्र, सीसीएल में कार्यरत थे, की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा देवी को रू.4,50,000/- का चेक प्रदान किया। स्व. बिन्देश्वरी प्रसाद का निधन विगत 06 मार्च, 2020 को हो गया था। इस अवसर पर सीसीएल ओबीएस के महासचिव राज कुमार सिंह, विनय कुमार शंकर, सुरेन्द्र प्रताप सिंह सहित उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

रांची रेल मंडल के सभी स्टेशनों पर निःशुल्क वाई-फाई की सुविधा

रांची :31 जुलाई 2020 को रांची रेल मंडल के टाटीसिल्वे स्टेशन पर वाई-फाई कमीशन के साथ ही रांची रेल मंडल के सभी 45 स्टेशनों पर निशुल्क वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है । निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से यात्री स्टेशन पर भी इंटरनेट संबंधित अपने कार्य कर पाएंगे। कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह निशुल्क वाई-फाई की सुविधा स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री ने मुंशी प्रमचंद को किया नमन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने महान लेखक एवं उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा शोषितों, वंचितों, किसानों और नारी जीवन से जुड़ी सामाजिक विसंगतियों को अपनी लेखनी से विश्व पटल पर ला कर समाज को जागृत करने का काम मुंशी प्रेमचंद ने किया था।

भविष्य में वैक्सीन के प्रभाव को कम कर सकती है बच्चों में आयरन की कमी

एक नए शोध से पता चला है कि यदि शैशव अवस्था में बच्चे के शरीर में आयरन की कमी हो तो वो भविष्य में टीकों के प्रभाव को कम कर सकती है।

यह जानकारी ईटीएच ज्यूरिख द्वारा किये शोध में सामने आई है। यह शोध जर्नल फ्रंटियर्स इन इम्म्युनोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी आई है और यह पहले की तुलना में कहीं ज्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है। इसके बावजूद अब भी हर साल करीब 15 लाख बच्चे उन बीमारियों के कारण मर जाते हैं जिनके टीके उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर मौतें कम आय वाले देशों में ही होती हैं। लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि आखिर क्यों टीकाकरण के बावजूद इन गरीब देशों के बच्चे इन बीमारियों का शिकार बन जाते हैं।

पहाड़ की चोटियों पर धान की खेती

सविन दास गोस्वामी

बंदगांवः पोड़ाहाट पहाड़ पर बसे लोग और श्रावण की बारिश का हमेशा से गहरा नाता रहा है. श्रावण की इसी बारिश में हरे होने लगते है झारखंड के पहाड़ो पर धान की बुआई के लिये लगाई जाने वाली रोपाई जिसे रोपनी भी कहते हैं, सामूहिक भागीदारी की प्रतीक है।

पोड़ाहाट के पहाड़ खेती के लिये पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं. यहां सबसे ज्यादा बारिश का महीना श्रावण है और इसी महीने यहां धान हरे भरे होते दिखते है. धान की बुआई के बाद पहाड़ के खेत किसी शानदार पेंटिंग से कम नहीं दिखते.

कुछ साल पहले तक श्रावण के महीने में आपको पहाड़ में घुटने तक कीचड़ में घुसे लोगों का समूह दिख जाता था इनके हाथ में हरे कोमल धान के पौधे होते. गीत गाते संग कमर झुकाये लोगों का यह समूह तेजी से अपने खेतों पर सरकता रहता. आज इस खेत, कल उस खेत.

धान की बुआई से पहले धान उसके पौधे किसी नमी वाली जगह पर उगाये जाते हैं गांव में रोपाई का दिन अलग-अलग घर के लिये अलग-अलग निश्चित रहता है. एक दिन में सभी गांव वाले मिलकर एक परिवार के खेतों में रोपाई लगाते हैं। उत्सव

के रूप में लगाई जाने वाली रोपाई के दिन सभी के खाने की व्यवस्था जिसके खेत

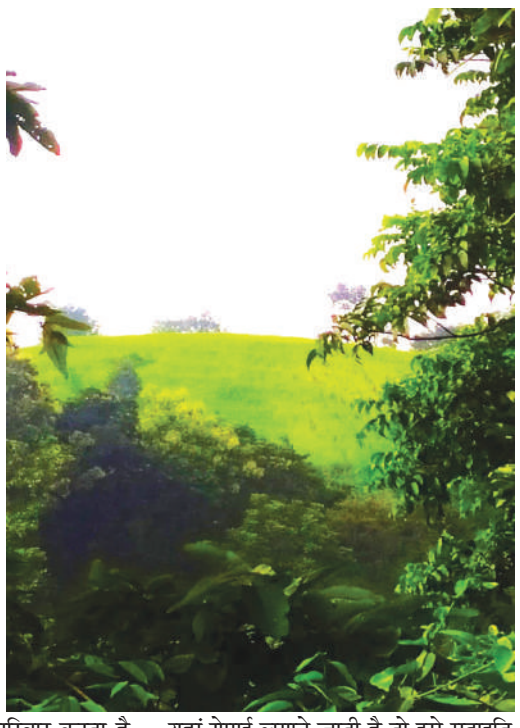

में रोपाई लगती है वह परिवार करता है. एक परिवार की महिलाएं दूसरे परिवार के यहां रोपाई लगाने जाती है तो इसे मदाइति कहते हैं।

रोहतांग पास में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का हुआ सफल परीक्षण

रोहतांग क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के सफल परीक्षण के बाद हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचआरटीसी) ने 25 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। वर्ष 2019-2020 के दौरान शिमला में और इसके आसपास प्रदूषण को कम करने और हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण के अनुकूल स-र्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 50 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गईं। 2020-2021 में एचआरटीसी का 100 और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का इरादा है। ये मनाली और रोहतांग पास के क्षेत्र में पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के सचिव की रिपोर्ट में उल्लिखित कुछ उपाय थे, जिन्हें लागू किया गया है।

खुले में जलाया जा रहा था वापी में औद्योगिक कचरा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण (जीपीसीबी) बोर्ड की संयुक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में जमा कर दी है।

इसमें जानकारी दी गई है कि सीपीसीबी और जीपीसीबी के अधिकारियों ने वापी में गुजरात औद्योगिक विकास निगम की चार पेपर मिलों का निरीक्षण किया था और वहां किस तरह से कचरे का निपटारा किया जाता है, इस बात की जानकरी ली थी। इसके साथ ही उन्होंने 13-15 नवंबर, 2019 के बीच उस क्षेत्र के आसपास भूजल की भी निगरानी और जांच की थी। इस जांच में शिकायतकर्ता यूनुस दाउद शेख ने भी 13 नवंबर, 2019 को रात के समय जीआईडीसी, वापी और आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण भी किया था। गौरतलब है कि कोर्ट को जानकारी दी गई थी कि वापी में रात के समय पेपर मिलों से निकले कचरा और स्क्रैप को जलाया जा रहा था, जिससे वायु प्रदूषित हो रही थी। इसके साथ ही वहां का भूजल भी केमिकल के कारण दूषित हो रहा है। इस कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रात के समय इसकी जांच के आदेश दिए थे। इन पेपर मिलों को पेपर बोर्ड/ क्राफ्ट पेपर जैसे उत्पादों के लिए डिंकिंग प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। इनसे बहुत ही कम मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट और ईटीपी स्लज उत्पन्न होता है। इसके निपटान के लिए पहले ही सीमेंट मिलों के साथ समझौता किया हुआ था। यह सीमेंट मिलें ईटीपी स्लज को वापस काम लायक सामान में बदल देती हैं। रिपोर्ट में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि जांच के समय इन यूनिट्स के परिसर में कोई ईटीपी स्लज जमा नहीं पाया गया।

हालांकि रिपोर्ट के अनुसार वहां रात के समय तीन अलग-अलग स्थानों पर बड़ी मात्रा में कचरे को अंधाधुंध जलते हुए देखा गया था। टीम ने जब अगली सुबह उस क्षेत्र का दौरा किया तो पता चला कि उस जगह पर विभिन्न प्रकार का औद्योगिक अपशिष्ट बिखरे हुए थे। इसके साथ ही वहां वाणिज्यिक क्षेत्र से निकले कचरे को भी उस क्षेत्र में फेंक दिया गया था। जांच टीम ने यह भी जानकारी दी है कि यह क्षेत्र आबादी से घिरा हुआ है।

सालाना कोयला जरूरतों का 20 प्रतिशत आयात करना पड़ता है

रांची : कोयलामंत्री प्रल्हाद जोशी ने व्यावसायिक कोयला खनन शुरू करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत को अपनी सालाना कोयला जरूरतों का लगभग 20% कोयला आयात के जरिए पूरा करना पड़ता है। व्यावसायिक कोयला खनन के शुरू होने के बाद स्वतंत्र एवं कैपटिव तापीय बिजली घरों द्वारा किए जाने वाले कोयला आयात को घरेलू कोयले की आपूर्ति से समाप्त किया जा सकेगा, जिससे सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आयात बिल की बचत होगी। साथ ही, इससे 03 लाख से अधिक कामगारों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने में भी मदद मिलेगी।

झारखंड के लिए खनन की महत्ता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि खनन राज्य की लाइफ लाइन है और उसके विकास में बेहद अहम भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां उसकी खनिजों से समृद्ध धरती से तीन-तीन कोयला कंपनियां कोयला खनन करती हैं। कोयला कंपनियां-ईसीएल, बीसीसीएल एवं सीसीएल अगले 04 वर्षों में झारखंड में लगभग 742 मिलियन टन (एमटी) कोयले का खनन कर राज्य को लगभग 18,889 करोड़ रुपए का राजस्व देंगी। गत 04 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपए, यानी 16,000 करोड़ रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। इन कोयला कंपनियों की होल्डिंग कंपनी, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), अपनी कुल देय रॉयल्टी का लगभग 30% अकेले झारखंड को भुगतान करती है, जबकि राज्य की सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 20% की हिस्सेदारी है। कोयला एवं खान मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार झारखंड की तरक्की और राज्य का देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान चाहती है। कोयला कंपनियां दशकों से झारखंड में कोयला खनन कर रहीं हैं और उसके बदले में राज्य के विकास के लिए राजस्व दे रही हैं। सीएमएसपी एक्ट के तहत आवंटित कोयला खदानों से झारखंड सरकार को सालाना 6,564 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल झारखंड में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी।

कोयला मंत्री ने 250 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा

- **कोयला खनन से विस्थापित होने वाले लोगों को बसाने के लिये और रैयतों को समुचित मुआवजे की मांग मुख्यमंत्री ने रखी ।**
- **मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को रॉयल्टी में हो रहे नुकसान और उसके भुगतान की मांग भी उठायी है।**
- **बंद हो चुके खदानों को पर्यावरण नियमानुसार समतल करके उस पर वृक्षारोपण करने के लिये भी केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया ।**

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड के विभिन्न जिलो में कोयला खनन से संबंधित विषयों पर बैठक हुई। बैठक में कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा कोल इंडिया के पदाधिकारी, मुख्य सचिव झारखंड, तथा राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे।

इस बैठक में राज्य सरकार कोल इंडिया द्वारा लिये गये 14296 एकड़ भूमि के एवज में 5439 करोड़ और 5298 एकड़ जंगल झाड़ी भूमि के लिये 2787 करोड़ रूपये का मुद्दा उठाया गया। कोल इंडिया ने राज्य सरकार की जितनी भी भूमि ली है उसके एवज में आज तक कोई भूगतान राज्य सरकार को नहीं किया गया है । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को लगातार छह महिने से भारत सरकार के समक्ष उठाया है और उसी के परिणाम स्वरूप कोयला मंत्री ने 250 करोड़ का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा और शेष राशि के भुगतान की भी बात कही है साथ ही सरकारी भूमि के एवज में कोल इंडिया लि. द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि से संबंधित मांग भी शीघ्र भेजने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सकों से मिले कोयला मंत्री गांधीनगर अस्पताल में

रांची : कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी गांधीनगर अस्पताल के चिकित्सक टीम से मिले । उन्होंने जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुण्डा के साथ सीसीएल के केन्द्रीय अस्पताल गांधीनगर जाकर सीसीएल की मेडिकल टीम से भेंट करके उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर अध्यक्ष कोल इंडिया प्रमोद अग्रवाल, सीएमडी, सीसीएल गोपाल सिंह, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव सहित केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर के सीसीएल सीएमएस डॉ सी.पी. धाम, डॉ. डीकीएल चौहान, डॉ मंजू मिश्रा, डॉ रत्नेश जैन एवं अन्य चिकित्सक सहित पारा मेडिकल स्टॉफ सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये उपस्थित थे।

प्रल्हाद जोशी ने अस्पताल में चल रहे कोविड मरीजों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी कोल वारियर्स यानि मेडिकल टीम, सफाई कर्मी का साधुवाद करते हुये कहा कि आप सभी कोराना संकटकाल में भी आप अपने दायित्व को पूरी समर्पण और सेवा भाव के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने अस्पताल कोरोना वारियर्स से मुलाकात की, मानव जाति की सेवा के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन किया। अर्जुन मुण्डा ने कोरोना मरीजों के शत-प्रतिशत इलाज के लिए सभी चिकित्सा एवं सफाई वारियर्स को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुये कामना किया कि इलाजरत सभी मरीज भी स्वस्थ्य होकर शीघ्र अपने घर जायें।

पर्यावरण मुकदमें एवं अदालती आदेश

एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 707 बस्तियां आर्सेनिक प्रभावित

27 जुलाई 2020 को जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंप दी है। मामला उत्तरप्रदेश में आर्सेनिक के कारण भूजल में बढ़ते प्रदूषण से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, राय बरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, संत रविदास नगर, उन्नाव और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिले में भूजल आर्सेनिक के कारण दूषित हो चला है। इसके साथ ही यहां पीने के साफ़ पानी की भी भरी किल्लत है जिस वजह से यह जिले 2015 से ही नजर में हैं।

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 707 जगह आर्सेनिक प्रभावित हैं। जिनमें से 164 निवास स्थान ऐसे हैं जहां अब तक पाइप वाटर नहीं पहुंच पाया है। जिनमें से 44 बस्तियों में दिसंबर 2020 तक पाइप लाइन का काम पूरा हो जाएगा जबकि 45 बस्तियों में मार्च 2021 तक पाईप लाइन जरिए जल की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसके अलावा 120 बस्तियों को सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) द्वारा कवर करने का प्रस्ताव रखा गया है। आर्सेनिक प्रदूषित बस्तियों में हैंडपंपों को हटाने का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है जो अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगले 3 महीनों के अंदर प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और 6 महीने के अंदर उसे दूर करने के लिए एक माइक्रो प्लान एनजीटी में पेश किया जाना चाहिए। इसके साथ ही रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की है कि कृषि विभाग द्वारा भी एक अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे फूड चेन पर इसके प्रभाव को समझा जा सके। साथ ही 6 महीने के अंदर इसके इम्पैक्ट असेसमेंट प्लान को तैयार कर सकते हैं और कृषि पदत्ति और क्रॉपिंग पैटर्न में भी बदलाव किया जा सकता है, जिससे इसके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सके।

प्रदूषण की जांच के लिए एनजीटी ने समिति को दिया अतिरिक्त समय

एजेंसियां : थर्मल पावर प्लांट और कोयला वॉशर के कारण हो रहे प्रदूषण की जांच के लिए समिति ने एनजीटी से अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे कोर्ट ने 28 जुलाई को स्वीकार कर लिया है।

मामला छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के तमनार और घरघोड़ा ब्लॉक का है। जहां थर्मल पावर प्लांट और कोयला वॉशर के कारण होने वाले प्रदूषण की जांच के लिए एनजीटी ने एक जांच समिति गठित की थी। यह बिजली संयंत्र और कोयला वाशरियां मैसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, मैसर्स जिंदल पावर एंड स्टील लिमिटेड, मैसर्स टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स महावीर एनर्जी एंड कोल बेनेफिकेशन लिमिटेड, मैसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स मोनेट एनर्जी लिमिटेड, एस-ईसीएल के हैं।गौरतलब है कि कथित तौर पर इन इकाइयों से हवा, पानी और जमीन दूषित हो रही थी। वहीं पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। वहां पानी और मिट्टी में जहरील धातुएं मिली हैं जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा हैं। यही वजह है कि इनसे हो रहे उत्सर्जन की निगरानी करना जरुरी है। साथ ही प्रदूषण की जवाबदेही भी तय करना जरुरी है और इसको रोकने के उपाय करना भी आवश्यक है।

रिपोर्ट में थर्मल पावर प्लांटों में इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) और फ्यूल गैस डी-सल्फराइजेशन सिस्टम (एफजीडी) की स्थापना का सुझाव दिया था। साथ ही भूजल में आ रही गिरावट, मृदा प्रदूषण, जंगलों के हो रहे विनाश और रोजगार पर पड़ रहे असर को भी नजरअंदाज नहीं करने के लिए कहा है।अदालत ने कहा है कि इन प्लांट्स में किसी भी तरह के विस्तार या नई परियोजनाओं को केवल गहन मूल्यांकन के बाद ही अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही प्रदूषण को कम करने के उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर और उसको रोकने के उपायों पर भी ध्यान देना चाहिए।

हरियाणा में सॉलिड वेस्ट न निपटाने पर एनजीटी ने जतायी नाराजगी

एनजीटी ने हरियाणा के अधिकारियों द्वारा सॉलिड वेस्ट के लिए किए जा रहे कामों पर नाराजगी जताई है। मामला हरियाणा के सिरसा में डबवाली से जुड़ा है। जहां वैज्ञानिक तरीके से सॉलिड वेस्ट का निपटान नहीं किया जा रहा है। राज्य द्वारा 15 जुलाई को एक रिपोर्ट दायर की गई है जिस-के अनुसार सॉलिड वेस्ट के निपटान का काम वैधानिक नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है।एनजीटी ने इसे ठीक करने के लिए अधिकारियों को एक 'अंतिम अवसर' दिया है। साथ ही वेस्ट को रोकने के लिए जरुरी और कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी, 2021 को की जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति अनुपालन के लिए हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को भेजी जाए।

प्रदूषण ने पांच साल कम कर दी है आपकी आयु

निशांत सक्सेना

●शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च की मानें तो बीते दो दशक में भारत में 46 प्रतिशत बढ़ा है प्रदूषण और जीवन जीने के लिए जिस गुणवत्ता की हवा चाहिए, उस मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरा नहीं उतरता है।

●अगर देशभर में 25 प्रतिशत तक प्रदूषण कम किया जाये, तो राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा में 1.6 साल और दिल्ली के लोगों के जीवन प्रत्याशा में 3.1 साल की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

दुनियाभर में कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़ मची हुई है। लेकिन एक और दुश्मन है जो हर दिन अरबों लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, वह है वायु प्रदूषण। शिकागो यूनिवर्सिटी की ओर से जारी नए एक्यूएलआई रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक हवा में तैर रहे पार्टीकुलेट मैटर कोविड से पहले इंसानों के स्वास्थ्य को कमजोर कर रहा था। और अगर आनेवाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर नहीं की गई, तो कोविड के बाद भी यह मानव जीवन प्रत्याशा को और बुरी तरह प्रभावित करेगा।

बात भारत की करें तो यहां जीवन प्रत्याशा पांच साल कम हो गई है। यानी एक औसत भारतीय वायु प्रदूषण की वजह से अपने जीवन के पांच साल कम जीने को मजबूर है। साथ ही, भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा प्रदूषण को झेलने के लिए भी मजबूर हैं। दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित नहीं है। वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक (एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स-एक्यूएलआई) यानी जीवन जीने के लिए जिस गुणवत्ता की हवा चाहिए, उस मामले में भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों

पर खरा नहीं उतरता है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों में भारत में पार्टीकुलेट मैटर (कण प्रदूषण) में 42 प्रतिशत की तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। आज भारत में 84 प्रतिशत लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, जो भारत के स्वयं के वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक प्रदूषित हैं। वहीं पूरी आबादी डबल्यूएचओ की ओर से तय मानक से अधिक के स्तर के वायु गुणवत्ता वाले माहौल में जीने को विवश हैं। नतीजतन, औसत भारतीय अपना जीवन पांच साल कम जीते हुए देखे जा सकते हैं। डबल्यूएचओ के मानक के मुताबिक पांच साल आयु कम हो रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय मानक के मुताबिक दो साल कम हो रहे हैं। इस बीच, भारत की जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा जिस प्रदूषण स्तर में जी रहा है, दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं देखा गया है। डबल्यूएचओ के मानकों पर खड़ा न उतरने की वजह से उत्तर प्रदेश के 230 मिलियन लोगों का जीवन आठ साल कम हो गया है। वहीं दिल्ली के निवासी भी अपने जीवन में 9 साल अधिक देख सकते थे। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि प्रदूषण के स्तर को डबल्यूएचओ के मानक के अनुसार रख कर बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी आम जन के जीवन को सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं हरियाणा के लोगों का जीवन आठ साल तक बढ़ाया जा सकता है।

कोविड के साथ प्रदूषण कम करने पर भी देना होगा खासा ध्यानः ग्रीनस्टोन

मिल्टन फ्रीडमैन प्रोफेसर और एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के निदेशक, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन कहते हैं, ''कोरोना वायरस का खतरा काफी है। इसपर गंभीरता से ध्यान देने आवश्यकता है। लेकिन कुछ जगहों पर, इतनी ही गंभीरता से वायु प्रदूषण पर ध्यान देने की जरूरत है। ताकि करोड़ों-अरबों लोगों को अधिक समय तक स्वस्थ जीवन जीने का हक मिले।'' माइकल ग्रीनस्टोन ने ही शिकागो यूनिवर्सिटी में ऊर्जा नीति संस्थान (ईपीआईसी) में अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर एक्यूएलआई की स्थापना भी की है। वह आगे कहते हैं, वास्तविकता यह है कि फिलहाल जो उपाय और संसाधन भारत के पास है, उसमें वायु प्रदूषण के स्तर में खासा सुधार के लिए मजबूत पब्लिक पॉलिसी कारगर उपाय है। एक्यूएलआई रिपोर्ट के माध्यम से आम लोगों और नीति निर्धारकों को बताया जा रहा है कि कैसे वायु प्रदूषण उन्हें प्रभावित कर रहा है। साथ ही, प्रदूषण को कम करने के लिए इस रिपोर्ट का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने प्रदूषण से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनकैप) की घोषणा की। इसके माध्यम से साल 2024 तक 20-30 प्रतिशत तक प्रदूषण कम करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन एक्यूएलाई के अनुसार इस लक्ष्य को हासिल करने के साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार की आवश्यकता है।अगर देशभर में 25 प्रतिशत तक प्रदूषण को कम किया जाता है, तो एनकैप के लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही राष्ट्रीय जीवन प्रत्याशा में 1.6 साल और दिल्ली के लोगों के जीवन प्रत्याशा में 3.1 साल की बढ़ोत्तरी हो सकती है।

शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ गुजरात में चल रहा है शोध

भारत में राज्य सरकारें वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में पहले से ही प्रयासरत हैं। कण प्रदूषण के लिए दुनिया का पहला एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर गुजरात में चल रहा है। सूरत में चल रहे इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाले कण प्रदूषण को कम करने पर शोध कम लागत में ही चल रहा है। । ग्रीनस्टोन कहते हैं, "इतिहास उदाहरणों से भरा है कि कैसे मजबूत नीतियां प्रदूषण को कम कर सकती हैं, लोगों के जीवन को लंबा कर सकती हैं भारत और दक्षिण एशिया के नेताओं के लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। क्योंकि वे आर्थिक विकास और पर्यावरण गुणवत्ता के दोहरे लक्ष्यों को संतुलित करने के लिए काम करते हैं। सूरत ईटीएस की सफलता बताती है कि बाजार-आधारित लचीला दृष्टिकोण से दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल किया जा सकता है।

फोटो न्यूज

प्रकृति की गोद में बहता पेरवाघाघ

पूजा श्रीवास्तव

झारखंड में बहने वाली नदियां और झरने हमेशा से आस पास के राज्यों के लोगों का आकर्षण का केन्द्र रहे हैं। पर अभी भी बहुत से ऐसे झरने है जो खूबसूरत तो बहुत हैं पर जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग ही वहां पहुंच पाते है, ऐसे ही झरनों में से एक है 'पेरवाघाघ'।

पेरवाघाघ झारखंड के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है । इसे कबूतरों का घर भी कहा जाता है। यह झरना दो नामों से बना है 'पेरवा' और 'घाघ'। स्थानीय भाषा में पेरवा का अर्थ कबूतर और घाघ का अर्थ घर है।आसपास के ग्रामीणों का कहना हैं कि कबूतरों का झुंड झरने के नीचे गुफा बना के रहता था। इसी कारण इसका नाम पेरवाघाघ पड़ा।

खूंटी जिले के तोरपा ग्राम में स्थित ये झरना खूबसूरत पहाड़ो और जंगलों से घिरा हैं। जिले में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक चतरा नदी से इस झरने की स्रोत निकलती है। मानसून के मौसम में इसका जलस्तर अधिक हो जाता है जिस कारण यह और भी सुंदर और रमणिक लगता है।सर्दियों में इसकी प्राकृतिक सुंदरता चरम सीमा पर होती है।

क्रिसमस और नए साल में भीड़ भार से दूर ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्थल है।लंबे समय तक यह पर्यटकों से अछूता रहा है लेकिन अब यह झारखंड में आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। जितना सुंदर ये झरना हैं उतना ही सुंदर रांची से यहाँ पहुँचने का मार्ग हैं। रांची जिले से इसकी दूरी लगभग 15 किमी हैं जो कि 1.5 से 2घंटे में आराम से पूरी की जा सकती हैं। मार्ग में पड़ने वाला बिरसा मृग बिहार और आमरेश्वर धाम मंदिर इस झरने तक की यात्रा को और सुखद और सुकूनमय बनाता है।

बढ़ते वज़न को नियंत्रित करने के उपाय

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

वज़न कम करने के लिए सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते है तो इसमे हमारी पूरी दिनचर्या आती हैं, जैसे आपके खाने–पीने का तरीका, सोने उठने का समय, आपकी दैनिक गतिविधि कितनी है इत्यादि। वज़न बढने का एक बहुत बड़ा कारण है कि जितनी कैलोरी आप भोजन से ले रहे हो उतना बर्न नहीं कर रहे हैं। इसके सरल भाषा में समझें तो आपका खाना ज्यादा हो रहा है और शारीरिक गतिविधियाँ कम हो रही है।

वज़न कम करने के कुछ उपाय

- अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा काफी रखें। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व हैं।वज़न कम करने में सहायक है क्योंकि प्रोटीन डाईट से पेट भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती हैं।
- हरी सब्जियां और सलाद खायें। हरी सब्जियां और सलाद लो कैलोरी होती है और फाइबर, विटामिन और खनिज से भरपूर होती है।
- व्यायाम करें। व्यायाम करने से शरीर का मेटाबोलिक रेट बढ़ता है यानि ये कैलोरी बर्न करने में सहायक होता है ।
- अच्छी नींद ले।अगर एक सही डाईट और व्यायाम के बाद भी वज़न कम नहीं हो रहा है तो फिर आपकी नींद अच्छी से नहीं हो रही है। अच्छी नींद भी वज़न कम करने के लिए जरूरी है।
- रात का खाना जल्दी खायें-सोने से कम से कम 3-4 घंटे पहले खाना खा ले और रात में हलका भोजन लेने की कोशिश करें।
- जंक फूड कम खाएं- आजकल जंक फूड खाने का जैसे ट्रेन्ड बन गया है। वज़न बढने का एक ये सबसे बड़ा कारण है ।
- ग्रीन टी का प्रयोग करे-ग्रीन टी मे भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैजो मेटाबौलिजम को बढ़ाने में मदद करता है। जो वज़न कम करने में काफी सहायक होता है।
- काली मिर्च और दालचीनी का प्रयोग खाने में करे- ये दोनों ही वज़न कम करने में सहायक है।
- दालचीनी को पानी में उबालकर उसमें थोड़ा सा शहद मिला कर पीये। ये आप सुबह खाली पेट या रात में सोने के समय ले सकते है।काली मिर्च पाउडर को अपने सलाद के ऊपर डाल के खाये या गुनगुने पानी में शहद डाल कर पीये।
- सेब का सिरका -एक चम्मच सेब का सिरके को गुनगुने पानी में मिलाकर के खाना खाने से थोड़ी देर पहले पीये। आप इसे सुबह खाली पेट भी ले सकते है।
- चीनी का प्रयोग कम करे- मीठा जितना कम हो सके उतना ही कम करे। आप चीनी की जगह पर गुड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इन कुछ छोटे छोटे-छोटे बदलाव से हम बढ़ते हुए वज़न को नियंत्रित भी कर सकते है और एक वज़न नियंत्रित होने पर उसे बनाये रख सकते है।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

समुद्र के बढ़ते जलस्तर से पूरी दुनिया है चिंतित

जलवायु परिवर्तन से समुद्र का जलस्तर बढ रहा है। जलस्तर के बढने से समस्या बेहद गंभीर होती जा रही है। इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) समुद्र के बढ़ते स्तर और एक्सट्रीम मौसम के नतीजतन आने वाली बाढ़ का क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर विश्लेषण कर चिंता जाहिर कर चुका है। आने वाले सालों में यह समस्या किस हद तक विकराल होगी, इसकी झलक 30 जुलाई को नेचर में प्रकाशित अध्ययन ''प्रोजेक्शन ऑफ ग्लोबल-स्केल एक्सट्रीम सी लेवल एंड रिजल्टिंग एपिसोडिक कोस्टल फ्लडिंग ओवर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी'' से मिलती है।

अध्ययन के मुताबिक, अगर कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन तेजी से जारी रहता है तो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले 80 सालों में दुनियाभर के समुद्र तटों पर होने वाली बाढ़ में 50 प्रतिशत इजाफा हो जाएगा। इससे लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। यह अध्ययन मेलबॉर्न विश्वविद्यालय और ईस्ट एंजिलिया विश्वविद्यालय (यूईए) द्वारा किया गया है। इसके अनुसार, दुनियाभर में अत्याधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर से वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि 48 प्रतिशत की होगी और इसी के साथ कुल प्रभावित क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो 21वीं शताब्दी के अंत तक 0.5 से 0.7 प्रतिशत वैश्विक भूमि पर समुद्री बाढ़ का खतरा मंडराएगा।

झीलों को प्रदूषण से बचाने के लिए बेंगलुरु में बन रहे हैं एसटीपी

एजेंसियां

बेंगलूरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) ने एनजीटी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जिसमें उसने इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह बेलंदूर, अगारा और वरथुर झील में सीवेज न बहाया जाए इस बात सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण का काम भी शुरू हो गया है जो 30 सितंबर, 2020 तक पूरा हो जाएगा। साथ ही सीवरेज नेटवर्क बिछाने और मौजूदा एसटीपी में बदलाव करके उन्हें जैविक पोषक तत्वों को हटाने के भी काबिल बनाया जाएगा। इसके साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि साफ किए गए जल को यूजीबी नेटवर्क में नहीं डाला जाए और न है ट्रीटेड सीवेज झीलों में बहाया जाए।

बीडब्ल्यू एसएसबी ने कहा है देशव्यापी लॉकडाउन के कारण 24 मार्च से 14 अप्रैल तक काम नहीं हो सका था। इसके अलावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार ने बेंगलुरु को रेड जोन में वर्गीकृत किया था। इस कारण प्रतिबंधों को 3 मई तक जारी रखा गया था। हालांकि गैर-जरूरी माल वाहनों की आवाजाही को अनुमति दी गई थी, लेकिन विनिर्माण इकाइयों के बंद होने के कारण निर्माण के लिए आवश्यक सीमेंट और स्टील की व्यवस्था नहीं की जा सकी थी।

बीडब्ल्यूएसएसबी ने कोर्ट को सूचित किया है कि एक्टिवेटिड सीवेज पर आधारित 150 एमएलडी क्षमता का नया एसटीपी जल्द ही पूरा हो जाएगा। कोरमंगला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 210 एमएलडी क्षमता का आईएसपीएस (मध्यवर्ती सीवेज पंपिंग स्टेशन) के निर्माण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन 150 एमएलडी एसटीपी के पूरा होने के बाद ही इससे सीवरेज पंप किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि चिक्कबगुरु में 5 एमएलडी एसटीपी और हुलीमावु में 10 एमएलडी एसटीपी का काम पूरा हो चुका है।

कोरोना से ठीक होने वालों में हृदय रोग का खतरा

एजेंसियां :

कोविड -19 की बीमारी से ठीक होने के लंबे समय के बाद ऑर्गन में खराबी जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं लेकिन इस पर विस्तृत अध्ययन की जरूरत हैकोरोनोवायरस बीमारी (कोविड-19) से उबरने वालों में हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। इस मामले में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल फ्रैंकफर्ट के एक अध्ययन ने कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान की है। शोध के मुताबिक 100 में से लगभग 80 ऐसे रोगियों के हृदय की एमआरआई जांच की गई, जो कोविड-19 से ठीक हुए थे। इनके हृदय में संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई दिए हैं।

जर्नल जेएएमए कार्डियोलॉजी में 27 जुलाई, 2020 को प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि कोविड -19 की बीमारी से ठीक होने के लंबे समय के बाद ऑर्गन में खराबी दिखाई देती है। यह ऐसे जगहों पर भी देखा गया जहां संक्रमण गंभीर नहीं था। बीमारी के पहले समूह के ठीक होने के दो महीने के बाद 100 संक्रमित रोगियों के एमआरआई की तुलना उन लोगों के साथ की गई थी, जो संक्रमण से नहीं गुजरे थे। 78 मरीजों के हृदय में पहले की स्थिति अलग संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई दिए। जब परीक्षण किया गया तो उनमें हृदय रोग संबंधी लक्षण मौजूद थे। 76 मरीजों में हृदयाघात के बाद होने वाली क्षति को भी देखा गया। वहीं, 60 मरीजों के दिल में सूजन का लक्षण दिखाई दिया। इन 100 मरीजों में से 67 घर पर थे, जबकि 33 को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। कम से कम 53 मरीज पुरुष थे जिनकी औसत आयु 49 वर्ष थी।

उसी दिन प्रकाशित, एक और अध्ययन में कोविड-19 से मरने वाले 39 लोगों , जिनकी औसत आयु 85 थी, के शव परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया गया। इसमें 24 रोगियों के दिलों में वायरस का उच्च स्तर पाया गया। अध्ययन के अनुसार: "सार्स-कोव-2" के साथ हृदय संबंधी संक्रमण इन रोगियों के बीच लगातार पाया गया , लेकिन यह मायोकार्डिटिस-जैसे कोशिकाओं के मायोकार्डियम (हृदय की मांसपेशी ऊतक) में शामिल नहीं था"। अध्ययन में कहा गया है कि हृदय संक्रमण वाले व्यक्तियों में, हृदय की मांसपेशियों की सूजन तीव्र चरण में नहीं देखी गई थी, लेकिन इस हृदय संक्रमण के दीर्घकालिक परिणामों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता" है।

वैलेंटिना पुंटमैन, ने कहा कि यह तथ्य कि 78 प्रतिशत ठीक होने वाले रोगियों में हृदय संबंधी रोग बहुमत में शामिल है, भले ही कोविड-19 बीमारी के साथ यह सीने में दर्द जैसे दिल की बीमारी के लक्षण को न शामिल किया जाता हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बीमारी की स्पष्ट शुरुआत सक्रिय कार्रवाई करने के लिए एक प्रारंभिक खिड़की खोलती है।

कभी पी है प्याज से बनी चाय?

मिताली जैन

प्याज की चाय से स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ होते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में यह विशेष रूप से लाभदायी है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि हाई बीपी के कारण लोगों को अक्सर हृदय संबंधी समस्याएं, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

हम में से कई लोगों की आदत होती है कि दिन की शुरूआत में हम चाय का सेवन करते हैं। अगर सुबह-सुबह चाय ना मिले तो ऐसा लगता है मानो दिन शुरू ही ना हुआ हो। लेकिन खाली पेट अगर दूध वाली चाय का सेवन किया जाए तो इससे एसिडिटी, हार्ट बर्न, कब्ज व अन्य कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए लोग चाय से दूर रहने की सलाह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय सिर्फ एक तरह से नहीं, बल्कि कई तरीकों से बनती है। आपने ग्रीन टी, ब्लैक टी या हर्बल टी का नाम तो सुना होगा लेकिन क्या आपने प्याज की चाय के बारे में सुना है। शायद नहीं। प्याज की मदद से भी चाय को तैयार किया जाता है। इससे आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। खासतौर से, यह

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में..

क्या कहता है अध्ययन

ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रीशन में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, अगर प्याज की स्किन से बनने वाले सप्लीमेंट्स को डाइट में शामिल किया जाए तो इससे उच्च रक्तचाप वाले लोगों के लिए रक्तचाप कम हो सकता है। ऐसे में अगर आप फूड सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो प्याज की चाय पीना अच्छा विचार है। वैसे भी प्याज की चाय हाइपर-टेंशन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है।

ऐसे होती है फायदेमंद

वैसे तो प्याज की चाय से स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ होते हैं, लेकिन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में यह विशेष रूप से लाभदायी है। हेल्थ एक्सपर्ट बताते हैं कि हाई बीपी के कारण लोगों को अक्सर हृदय संबंधी समस्याएं, दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में दवाइयों के अलावा आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। इन्हीं में से एक है प्याज की चाय। दरअसल, प्याज में फ्लेवोनॉल और क्वेरसेटिन घटक होते हैं जो आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा कुछ अध्ययन यह भी बताते हैं कि प्याज की चाय पीने से आप दिल की बीमारियों से भी दूर रहते हैं।

यूं बनाएं चाय

अब सवाल यह उठता है कि प्याज की चाय को किस तरह तैयार किया जाए तो इसे बनाना काफी आसान है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। प्याज की चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में आधा कप पानी डालें। इसके बाद आप इसमें कटी हुई प्याज, क्रश्ड लहसुन, लौंग व तेजपत्ता डालें। अब इसे थोड़ा सा पकने दें। जब पानी का रंग गहरा होने लगे तो गैस बंद कर दें। अब आप इसे छलनी की मदद से छान लें। आप इसमें अपने स्वादानुसार शहद, दालचीनी पाउडर या नींबू का रस भी मिला सकते हैं।

इस रेसिपी में नींबू का रस, तेज पत्ता व दालचीनी पाउडर ऑप्शनल है। ●

चार धाम मार्ग परियोजना में हुई है बड़ी पर्यावरणीय चूक

एसपी सती

भारत सरकार द्वारा चारधाम राजमार्गों के सुधारीकरण के लिये विशेष योजना का शिलान्यास और 12 हजार करोड़ का आर्थिक पैकज जारी करना निश्चित ही एक प्रशंसनीय कदम था। किन्तु इसके सफल क्रियान्वयन के लिये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके शिल्पकारों के ऊपर थी जिन्हें भूस्खलन, भू-धंसाव और भूकंप संवेदी अति-संवेदनशील चारधाम हिमालयी घाटियों में परियोजना के स्वरुप को तैयार करना था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर गठित हाई पावर कमिटी ने अपनी रिपोर्ट के 10 अध्यायों में एक-मत रूप से विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों जैसे पहाड़ी ढालों के कटान और भूस्खलन, जल-श्रोतों पर प्रभाव, वन्यजीवों के संज्ञान, सामाजिक जन-जीवन पर प्रभाव, वन-क्षेत्र और मलबा निस्तारण के प्रभाव और आपदा प्रबंधन से सम्बंधित तमाम तथ्य उजागर किये हैं। नये उभरे भू-स्खलन क्षेत्रों और भारी मलबे के अवैज्ञानिक निस्तारण से उत्पन्न खतरे की विभीषिका पर भी निर्माणकारी संस्थाओं और सड़क मंत्रालय को समय समय पर तत्काल सुरक्षात्मक कार्यों के लिये भी कहते रहे।

आजकल बरसात शुरू होते ही तमाम वो समस्याएं भूस्खलन और गलत रूप से निस्तारित मलबे के कारण मुखर होने लगी हैं। आए दिन चारधाम मार्ग तमाम जगहों पर भूस्खलनों के सक्रिय होने से बाधित हो

रहा है और भारी मलबा स्थानीय जनमानस के जान-माल की हानि का सबब बन रहा है।

चारधाम सड़क चौड़ीकरण की परियोजना में तत्कालीन समय (2015-16) में अपनाये मानक (डीएल-पीएस, 12 मीटर) चारधाम घाटियों के पहाड़ी ढालों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। यह बात राजमार्ग मंत्रालय की प्लानिंग ज़ोन ने भी वर्ष 2018 में स्वीकार ली थी तथा मार्च-2018 में एक सर्कुलर निकाल पहाड़ी क्षेत्रों के लिए इन्हे संशोधित कर दिया था। संशोधित मानकों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई के मानक इंटरमीडिएट लेन (7-8 मीटर) कर दिए गए थे, किन्तु फिर भी चारधाम योजना में पुराने हानिकारक मानकों (डीएल-पीएस) के तहत ही चौड़ीकरण जारी रखा गया। इस नए सर्कुलर को न्यायालय तथा कमिटी के संज्ञान में भी अंत तक नहीं लाया गया। चारधाम घाटियों में स्थानीय जरुरत, यात्रा काल तथा सेना वाहनों की आवाजाही के लिए राजमार्ग सुधारीकरण में तीन बातें महत्व की हैं:-

1- मार्ग का आपदा के नजरिये से सुरक्षित होना।

2- मार्ग के किनारे हरित क्षेत्र/पेड़ों का रहना ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूस्खलनरोधी दृष्टि से भी मार्ग अनुकूल बने।

3- स्थानीय जनों, तीर्थयात्रियों के लिए परम्परागत पैदल यात्रा/आवागमन की अनुकूलता का ध्यान रखा जाए।

पुराने मानक के अनुसार अत्यधिक चौड़ीकरण के लिए बहुत अंदर तक (आम तौर से 24 मीटर तक) पहाड़ी ढलानों का कटान करने के कारण कई भूस्खलन क्षेत्र पैदा हो गए हैं। पहाड़ी कटान अधिक होने से मलबा भी अधिक पैदा हो रहा है और इसका निस्तारण घाटियों में ही होने के चलते मलबे के बड़े-बड़े ढेर भी आपदा का सबब बने हुए हैं। स्थानीय जरुरत, सेना वाहनों तथा यात्रा की जरुरत हेतु इन घाटियों में 7-8 मीटर चौड़ी सड़क पर्याप्त है। इसमें कोई दो राय नहीं कि डबल लेन-पीएस अर्थात 12 मीटर चौड़ी सड़क (10 मीटर काली सतह के साथ) बनाने के लिए भारी तादात में पहाड़ी के कटान की जरुरत होती है और वही सड़क के मानक यदि इंटरमीडिएट लेन अर्थात 8 मीटर (5.5 मीटर काली सतह के साथ) कर दिये जायें तो लगभग 70-80 प्रतिशत नुकसान कम कर और अधिकांश भाग में तो बिना किसी कटिंग के उक्त सड़क का सुधारीकरण अधिक गुणवत्ता, कम लागत और पर्यावरणीय अनुकूल ढंग से किया जा सकता है।

चारधाम परियोजना के लिए आवंटित राशि में तो आधुनिक तकनीक द्वारा पहाड़ी ढालों को कम से कम छेड़ते हुए घाटी की तरफ से दीवारें, पुलनुमा संरचनाएं बना कटान व भरान तरीके से इंटरमीडिएट मानक के अंतर्गत सुरक्षित रूप से सड़क का उच्चीकरण किया जा सकता था। पैदल यात्रियों, साधुओं, तीर्थयात्रियों, स्थानीय जनों के लिए साथ में एक सुन्दर आस्था-पथ का निर्माण भी 8 मीटर सड़क के भीतर कर हरा-भरा मार्ग तैयार हो सकता था। किन्तु पुराने मानक (डीएल-पीएस) के अनुसार 12 मीटर चौड़ाई प्राप्त करने के लिए एक तरफ़ा पहाड़ी कटान का तरीका अपनाया गया, क्योंकि घाटी की तरफ से इतनी अधिक चौड़ाई आम तौर से प्राप्त करना बहुत कठिन, खर्चीला और कम-गुणवत्ता युक्त काम होता। परिणामस्वरूप उत्पन्न मलबे की डम्पिंग के लिए भी भूमि का अधिग्रहण अलग से करना पड़ा और घाटियों में नदियों, जलधाराओं के मार्ग में बड़े-बड़े डम्पिंग ज़ोन तैयार हो गए जो अब बरसात में कई स्थानों पर किसी बड़ी आपदा का कारण बने हुए हैं।

E ZONE CARE

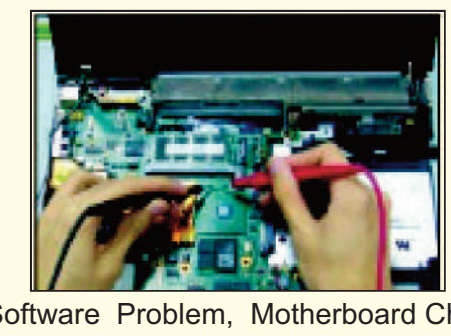

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।